

श्रीमति उर्मिला बिमनभाई पटेल: मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करती हूँ कि जो फाइल पड़ी हुई है उसको भी निकाला जाये और जो गुजरात की पुरानी बात है उसको एक्सेप्ट करें। और यह बैंक आफ बड़ौदा के ट्रान्सफर पर अकेले रोक न लगाई जाए, उसके चेयरमैन और सभी जो आफिसेज हैं उनको डाइरेक्ट का करने जो प्रोसेज हो रहा है, उसमें उनको बड़ौदा में ही रहने के लिए इंसिस्ट किया जाए, यही मैं विनती करती हूँ। धन्यवाद।

श्रीमती आनन्दीबेन जेटाभाई पटेल: मैं अपने को इससे संबद्ध करते हुए कहना चाहती हूँ कि आफिस बड़ौदा में ही रहना चाहिए, मुंबई में नहीं जाना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): उन्होंने दोनों मुद्दे उठा दिए। Now, we move on to Special Mentions.

### SPECIAL MENTIONS

Non-compliance of Supreme-Court's directive to Provide 27 per cent reservation to O.B.G.S. as per Mandal Commission's Recommendations by Union Public Service Commission

श्री नागमणि (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अति महत्वपूर्ण विशेष उल्लेख के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मंडल कमीशन की सिफारिशों को जो लागू करने की बात हुई थी, उसमें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने उसका खुल्लमखुल्ला पञ्जाक बनाया है। मंडल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि जो पिछड़ी जाति के छात्र मैरिट लिस्ट में आयेगे उनको सामान्य सूची में रखा जाएगा और उसके बाद मैरिट लिस्ट अलग से बननी चाहिए। जब कि सच्चाई यह है कि सामान्य सूची से जो मैरिट लिस्ट में आते हैं उसे की 27 प्रतिशत मंडल कमीशन में शामिल कर दिया जाता है। पिछले वर्ष का जो रिजल्ट आया है उसमें मात्र 27 प्रतिशत ही पिछड़ी जाति के छात्र आए हैं। इसका मतलब साफ है कि सामान्य सूची में एक भी छात्र जो पिछड़ी जाति का है, वह मैरिट लिस्ट में नहीं आया है। तो हमारा इसमें स्पष्ट कहना है कि जो मंडल कमीशन की सिफारिश है, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है, उसके आधार पर जो मैरिट लिस्ट है उसको सामान्य सूची में काटें नहीं किया जाए।

एक और बात की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। 17 अप्रैल, 1996 को मद्रास में कैंट का निर्णय हुआ है कि संघ लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण लागू रहेगा क्योंकि जब तक प्रारम्भिक परीक्षा में ही रिजल्ट नहीं निकलेगा तो मेन एक्जामिनेशन में कैसे बैठ सकता है। लेकिन आश्चर्य है कि...

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): आपने अपनी पूरी बात कह दी। उसके विस्तार में न जाए। अभी आपको इस पर बोलने का मौका मिलेगा। बजट डिस्क्शन के समय आप इसको उठा सकते हैं।

श्री नागमणि: लेकिन आश्चर्य है कि जब 13 दिनों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो वह मद्रास की कैंट ब्रांच के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए जिससे देश की पिछड़ी जाति के जो 52 प्रतिशत छात्र हैं उनमें काफी आक्रोश है, इसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

श्री रामदेव भंडारी (बिहार): महोदय, जो सवाल नागमणि जी द्वारा उठाया गया है, जो ओम्बीन्सी के रिजर्वेशन के बारे में हैं, इस सवाल के साथ मैं अपने आप को संबद्ध करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि रिजर्वेशन के पीछे जो उद्देश्य सरकार का था और है, उसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने किसी न किसी कारण से उसका उल्लंघन किया है। प्राइमरी टेस्ट जो होता है, उस टेस्ट में जो पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार जनरल कंडीटेंट्स के साथ कंपीट करते हैं, उनको उनके साथ न रखकर उनको भी 27 प्रतिशत के अन्तर्गत लाया जाता है। तो यह उनके साथ अन्याय है। जो उम्मीदवार आम कंडीटेंट्स के साथ कंपीट करते हैं उनको भी इसके अन्तर्गत रख लेते हैं। जो कंडीटेंट आम छात्रों के साथ कंपीट नहीं करते हैं केवल उनको ही 27 प्रतिशत आरक्षण के अंदर लाना चाहिए। इसलिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से निवेदन करूंगा कि एक स्पष्ट नोटिफिकेशन इस संबंध में वह यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को दे और उनको इस बात की ताकीद करे कि जो उम्मीदवार सामान्य कोटि में कंपीट करते हैं उनको रिजर्वेशन कोटि में न रखा जाए। जो सामान्य कोटि में कंपीट नहीं करते हैं उनको ही 27 प्रतिशत के आरक्षण के अन्तर्गत रखा जाए। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Now, Shri Giri Prasad. He is not here. Shri S. M. Krishna— he is also not here right now. Shri Saifulla.

### Declaration of Anantpur District of Andhra Pradesh as drought-prone area

SHRI SAIFULLA (Andhra Pradesh): Respected Vice-Chairman, Sir, I come from Anantpur district of Andhra Pradesh. This is the place from where our former President, late Shri Neelam Sanjeeva Reddy, came. The famous Puttaparthi Sai Baba also resides in that district.

I am very sorry to bring to the notice of the Government that even though a survey declared Bharatpur district in Rajasthan and Anantpur district in Andhra Pradesh as drought-prone districts, our district has not been declared by the Government as a drought-prone district. The survey has brought this matter to the notice of the Government of India also. In Anantpur district, there is a catchment area. But there are no trees. There are no living streams. There is no water in the streams that are there. As a result, there is not much of a forest cover. Because of all this, the rainfall in the district is very much below the national average. The water-table has gone down by more than 300 feet. The worst sufferers are the farmers. Even though they dig bores deep into the ground, they are not able to get water. That is the fate of Anantpur district. The groundwater level came down drastically. For doing anything, there is a big constraint—lack of funds. When we represented the matter to our hon. Chief Minister, Chandra Babu Naidu Garu, he was kind enough to release some funds for social forestry purposes, which could be useful for drawing rains. With these funds, we are also undertaking planting of trees. But, as you are aware, even the Government of Andhra Pradesh is under financial constraints because of huge rice subsidy and also because of introduction of prohibition. The meagre funds released by the Government of Andhra Pradesh is not at all sufficient to undertake various works, especially those relating to improvement of groundwater level. Added to this pitiable condition is the fact that there are no industries in the district.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Mr. Saifulla, your Special Mention is about declaration of Anantpur district as a drought-prone district. I request you to confine yourself to the subject.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, it is his maiden speech.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): I think it is his second maiden speech. He spoke already.

SHRI SAIFULLA: Mr. Vice-Chairman, Sir, I can understand your feelings. I would conclude shortly.

Establishment of industries could help the district economically. We should not let the

district remain backward endlessly.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): As I understand, your subject is about declaration of Anantpur district as a drought-prone district. It is a very important matter. Don't deviate from the subject.

SHRI SAIFULLA: Sir, I am sorry if I am deviating from the subject. I request the Government of India, through you and through Rajya Sabha, to declare Anantpur district as a drought-prone district immediately.

In this connection, I would like to acknowledge my grateful thanks to Shri Puttaparthi Sai Baba—who came forward voluntarily and provided some funds to construct water tanks. But what is the use? There is no water in the tank which was constructed by Shri Sai Baba. His dream could not be fulfilled. After all, we get water from the TP tank only for three months. I am saying all this only to enable you to understand the gravity of the situation. After hearing me, please draw your own conclusions.

My only request to the Government of India is to help Anantpur district by granting sufficient funds to develop the district. I request the Union Government to declare Anantpur district as a drought-prone district immediately. In addition to this, I request the Central Government to increase the allocation of houses to be constructed under the Indira Awas Yojana. Finally, I request the Government to initiate such steps as to develop the district in all respects.

Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir.

**Telephone link on Parwanu to Shirala and Kalka - Chandigarh Panchkula - Kharar Sector**

SHRI LACHHMAN SINGH (Haryana): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for giving me this opportunity. This is my maiden speech. I was elected unopposed to this House from Haryana in February, 1996.

I would like to bring to your kind notice a very important issue concerning more than ten lakh people. Kalka is the last station of Haryana. I request the hon. Minister to take note of what I am saying because there are many glaring lapses on the part of the Department of Telecommunications.